हरिभूमि
विराट भूमि
शहडोल | बुढ़ार | धनपुरी | ब्यौहारी | जयसिंहनगर | बाणसागर
जबलपुर, शुक्रवार 3 जुलाई 2026
login : www.haribhoomi.com

खबर संक्षेप

17 वर्षीय किशोर की नदी में डूबने से मौत

शहडोल। प्रशासनिक चेतावनियों को हवा में उड़ाने और बारिश के मौसम में उफनती नदियों के प्रति बरती जा रही घोर लापरवाही ने जिले में एक और मासूम की जिंदगी छीन ली। पपौंध थाना क्षेत्र के बड़ी खारी गांव में दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जहां सोन नदी में नहाने गया 17 साल का एक किशोर गहरे पानी की भेंट चढ़ गया। मिली जानकारी के मुताबिक, बड़ी खारी निवासी विप्र साकेत उम्र 17 वर्ष अपने कुछ दोस्तों के साथ दोपहर को सोन नदी में नहाने पहुंचा था। मौज-मस्ती के फेर में किशोर बिना गहराई का अंदाजा लगाए नदी के उस खतरनाक और गहरे हिस्से में उतर गया, जहां साक्षात मौत उसका इंतजार कर रही थी। किनारे खड़े दोस्तों ने जब उसे आंखों के सामने जिंदगी की जंग लड़ते देखा, तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने बचाने का प्रयास किया और शोर मचाया, लेकिन जब तक आसपास के ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे, तब तक विप्र नदी के गहरे पानी में हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। घटना की सूचना मिलते ही पपौंध थाना पुलिस आनन-फानन में मौके पर पहुंची।

विकसित भारत जी राम जी योजना में मिला श्रम, सम्मान और विकास: शरद कोल

ग्रामों के विकास से ही देश का विकास संभव: विधायक

विकसित भारत जी राम जी योजना का किया गया औपचारिक शुभारंभ

शहडोल।

भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई से प्रारम्भ की गई विकसित भारत जी राम जी योजना का जिला स्तरीय औपचारिक शुभारंभ जनपद पंचायत जयसिंहनगर में विधायक जयसिंहनगर श्रीमती मनीषा सिंह एवं विधायक ब्यौहारी शरद कोल ने भारत माता के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर किया। विधायक श्रीमती मनीषा सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा विकसित भारत जी राम जी योजना 1 जुलाई से प्रारंभ की गई है। यह योजना श्रमिकों के लिए आर्थिक रूप से सशक्त बनाने एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने तथा अधोसंरचना निर्माण के लिए नए स्वरूप में प्रारंभ की गई है।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी रामजी योजना का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने एवं लोगों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए पंचायत विभाग के मैदानी अमले की भूमिका अहम होती है। इस योजना का लाभ श्रमिकों को दिलाने के लिए मैदानी स्तर पर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ग्रामों का विकास एवं श्रमिकों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत होती है।

विधायक शरद कोल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश में विकसित भारत जी रामजी योजना का प्रारंभ नए स्वरूप में किया गया है जो समय के साथ बदलने की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को उनके परिश्रम के आधार पर उन्हें अब 300 रूपये की न्यूनतम मजदूरी एवं 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने विकसित भारत जी रामजी योजना के तहत निर्धारित की गई है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए किसानों, युवाओं,महिलाओं एवं समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी आवश्यक है। यह योजना श्रमिकों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी रामजी योजना में श्रमिकों को श्रम, सम्मान और विकास मिला है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने कहा कि बदलते दौर में रोटी, कपड़ा, मकान के साथ-साथ रोजगार की जरूरत होती है। 1 जुलाई से प्रारंभ विकसित भारत जी राम जी एक्ट श्रमिकों के लिए नया अध्याय प्रारंभ किया गया है।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो गया है। यह नया कानून ग्रामीण रोजगार और आजीविका सुरक्षा के लिए लाया गया है। रोजगार की कानूनी गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। पात्र ग्रामीण परिवार अब एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों तक मजदूरी आधारित रोजगार पा सकेंगे। तय समय में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान भी जारी रहेगा। ग्रामीण मजदूरों के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी 300 तय की गई है। सरकार ने समय पर वेतन भुगतान और डिजिटल निगरानी पर जोर दिया है। जिला स्तरीय कार्यक्रम में विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम को वर्चुअली रूप से देखा एवं सुना गया। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने विकसित भारत जी रामजी योजना के तहत सेवा देने वाले श्रमवीरों को फूल माला पहनाकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवम प्रजापति, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुश्री काजोल सिंह, उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती फूलवती सिंह, अध्यक्ष जनपद पंचायत श्रीमती मालती सिंह, श्रीमती आकांक्षी सिंह, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत श्रीमती रक्षा सिंह, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुद्रिका सिंह, सीईओ जनपद श्रीमती शिवानी जैन सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन जनजातीय कार्य विभाग के राजेंद्र तिवारी द्वारा किया गया।

गर्भवती माताओं की सतत निगरानी आवश्यक: सीएमएचओ

मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए दिए गए आवश्यक निर्देश

शहडोल।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश मिश्रा की अध्यक्षता में मासिक शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाने हेतु समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अप्रैल से जून 2026 के दौरान जिले में हुई तीन मातृ मृत्यु के प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए उनके कारणों, स्वास्थ्य सेवाओं में सामने आई कमियों एवं आवश्यक सुधारात्मक उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश मिश्रा ने कहा कि मातृ मृत्यु की प्रत्येक घटना अत्यंत संवेदनशील है और इसे रोकने के लिए स्वास्थ्य तंत्र को और अधिक सक्रिय एवं जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए कि समीक्षा के दौरान चिन्हित सभी कमियों को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल दूर किया जाए तथा गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान, नियमित प्रसवपूर्व जांच, एनीमिया एवं अन्य जटिलताओं की समय रहते पहचान, उच्च जोखिम गर्भावस्था का प्रभावी प्रबंधन, समय पर रेफरल व्यवस्था तथा शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। साथ ही आशा, एएनएम एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को समुदाय स्तर पर सतत निगरानी एवं जागरूकता गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए गए, ताकि भविष्य में मातृ मृत्यु की घटनाओं में प्रभावी कमी लाई जा सके। बैठक में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.के. शुक्ला, सिविल सर्जन डॉ. शिल्पी सराफ सहित जिला स्वास्थ्य समिति के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

शहडोल मेडिकल कॉलेज में प्रभार का मूक खेल

वरिष्ठता को दरकिनार कर जूनियर को सौंपी कमान

नर्सिंग ऑफिसर को मलाईदार पद सौंपने और हटाने के प्रशासनिक सर्कस से उठे गंभीर सवाल

शहडोल।

बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय इन दिनों मरीजों के इलाज से ज्यादा अपनी आंतरिक सियासत और म्यूजिकल चेयर के खेल को लेकर सुर्खियों में है। अपने चहेतों को उपकृत करने के लिए नियमों को ताक पर रखने और फिर विवाद गहराने पर रहस्यमयी तरीके से पैर पीछे खींचने का एक बड़ा मामला सामने आया है। करीब 100 से अधिक शिकायतों और मीडिया में लगातार खिंचाई के बाद आखिरकार कॉलेज प्रबंधन को झुकना पड़ा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में अधिष्ठाता (डीन) कार्यालय द्वारा जारी ताजा आदेश ने संस्थान के भीतर चल रही प्रशासनिक उठापटक और अपारदर्शिता की कलई खोलकर रख दी है।

पूरा मामला नर्सिंग स्टाफ की कमान नियमों के विपरीत एक जूनियर अधिकारी को सौंपने से जुड़ा है। सूत्रों की मानें तो जुलाई 2024 में वरिष्ठता और योग्यता की स्थापित सूची को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए नर्सिंग ऑफिसर दीपा रोहाणी कनौजिया को प्रभारी नर्सिंग अधीक्षक और प्रभारी मेट्रन का महत्वपूर्ण जिम्मा सौंप दिया गया था। इस मनमानी के खिलाफ कॉलेज के योग्य और सीनियर स्टाफ में भारी असंतोष था। लगातार हो रही विभागीय खींचतान और वर्चस्व की जंग की खबरें मीडिया में तैरती रहीं, जिससे अस्पताल की कार्यसंस्कृति पर बेहद बुरा असर पड़ रहा था। प्रबंधन की दोमुंही कार्यप्रणाली का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब नियुक्ति की गई (आदेश क्रमांक 854, दिनांक 18/07/2024), तब पत्र में स्पष्ट रूप से दीपा रोहाणी कनौजिया के नाम का उल्लेख था और उन्हें अटेंडेंस, ड्यूटी रोस्टर तथा स्टाफ मैनेजमेंट जैसे सभी महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए थे, लेकिन जब शिकायतों का अंबार लगा और जांच बैठी, तो 30 जून 2026 को अधिष्ठाता कार्यालय द्वारा एक नया आदेश (क्रमांक 5637) जारी कर पुराने आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि इस नए निरस्तीकरण आदेश में उस अधिकारी के नाम का जिक्र करने से साफ परहेज किया गया है जिसे पद से हटाया जा रहा है। केवल पुराने पत्र क्रमांक को निरस्त करने की खानापूर्ति की गई है। मेडिकल कॉलेज के गलियारों में चर्चा गर्म है कि यह कार्रवाई किसी नियम-कायदे की बहाली के लिए नहीं, बल्कि प्रबंधन के भीतर सक्रिय दो गुटों की आपसी जंग का नतीजा है। आरोप लग रहे हैं कि जब तक सेटिंग मनमुताबिक चलती रही, तब तक नियम दफन रहे, जैसे ही आपसी तालमेल बिगड़ा, जांच की ढाल बनाकर पद से मुक्त कर दिया गया। इस पूरे प्रशासनिक ड्रामे ने साफ कर दिया है कि शहडोल मेडिकल कॉलेज में मरीजों की सहूलियत से ज्यादा रसूख की जंग को अहमियत दी जा रही है। अब देखना यह होगा कि इस गुपचुप आदेश के बाद वाकई वरिष्ठ अधिकारियों को उनका हक मिलता है, या फिर किसी नए चहेते की ताजपोशी की पटकथा लिखी जा रही है।

बिजली दफ्तर की नाक के नीचे करंट से भैंस की मौत

शहडोल। सोहागपुर क्षेत्र के छतवाई बिजली कार्यालय के ठीक पास गुरुवार को करंट की चपेट में आने से एक भैंस की तड़प-तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई। बिजली दफ्तर की नाक के नीचे हुए इस हादसे से विभाग की घोर लापरवाही उजागर हुई है, जिसे लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक भैंस चरते हुए कार्यालय के पास पहुंची थी, तभी जमीन पर उतरे मौत के करंट ने उसे जकड़ लिया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, बेजुबान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस हादसे से गरीब पशुपालक को भारी आर्थिक चपत लगी है। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि जब बिजली विभाग अपने दफ्तर के आसपास के तारों और उपकरणों को सुरक्षित नहीं रख पा रहा, तो बाकी क्षेत्र का क्या हाल होगा, स्थानीय लोगों ने दोषियों पर कार्रवाई, निष्पक्ष जांच और पीड़ित पशुपालक को तत्काल उचित मुआवजा देने की मांग की है।

सीपीएम राजीव कुमार और सीनियर डीईएन अरविंद विश्वकर्मा सम्मानित

रेलवे मजदूर कांग्रेस ने किया अधिकारियों का सम्मान

शहडोल।

भारतीय रेलवे अब एक नए और आधुनिक दौर में कदम रख चुका है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन विकास योजना के तहत शहडोल, उमरिया और अनूपपुर स्टेशनों का कायाकल्प एक्सप्रेस की रफ्तार से हो रहा है। पुराने समय की संकरी और असुविधाजनक व्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए अब अत्याधुनिक सर्कुलेटिंग एरिया तैयार किया गया है। इसमें चौड़ी सडक़ें, यात्रियों के सुगम आवागमन के लिए रिंग रोड, आधुनिक लाइटिंग और वाहनों के लिए विशाल व सुविधाजनक पार्किंग का निर्माण शामिल है। राजनीतिक गलियारों और आम जनता के बीच इस अभूतपूर्व विकास की जमकर तारीफ हो रही है। विकास कार्यों को गति देने के लिए योजना के तहत हटाए गए पुराने पार्कों, रेलवे आवासों और कार्यालयों के बदले रेलवे कॉलोनी में नए पार्क, चमचमाते आवास और सर्वसुविधायुक्त कार्यालय बना दिए गए हैं। क्षेत्र में यह चर्चा आम है कि चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर (सीपीएम) राजीव कुमार के पदभार ग्रहण करते ही इन कार्यों में गजब की तेजी आई है।रेलवे सूत्रों के मुताबिक, योजना के दूसरे चरण में पुरानी स्टेशन बिल्डिंग के स्थान पर व्यावसायिक जरूरतों (कमर्शियल रिक्वायरमेंट) के हिसाब से एक आलीशान नवीन स्टेशन बिल्डिंग खड़ी की जाएगी। इसमें आधुनिक शॉपिंग मॉल, लग्जरी लाउंज, दुकानें और सर्वसुविधायुक्त विश्राम गृह बनाए जाएंगे। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए सक्षम अधिकारियों की अनुमति से सुलभ शौचालय आदि का निर्माण भी सर्कुलेटिंग एरिया में किया जाएगा।

अधिकारियों की इसी कार्यकुशलता और विकासपरक सोच को देखते हुए साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर कांग्रेस बिलासपुर ने उन्हें सम्मानित किया है। बीते 1 जुलाई को वरिष्ठ मंडल अभियंता समन्वयक (सीनियर डीईएन को-ऑर्डिनेशन) बिलासपुर अरविंद विश्वकर्मा के चेंबर में एक गरिमामयी कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें मंडल समन्वयक विजय अग्निहोत्री, जोनल कार्यकारी सीआईसी प्रभारी अध्यक्ष लक्ष्मण राव, अतिरिक्त संयुक्त महामंत्री शुभम उपाध्याय और रायगढ़ शाखा सचिव संजय श्रीवास्तव ने सीपीएम बिलासपुर राजीव कुमार एवं सीनियर डीईएन अरविंद विश्वकर्मा को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए संगठन की ओर से शाल-श्रीफल देकर सम्मानित किया। मजदूर कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि अधिकारियों की यह लगन क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित हो रही है।

शहडोल-अनूपपुर से यूपी के बूचडख़ानों तक जुड़ा है तस्करी का नेटवर्क

तस्करों पर रासुका लगाने और संभाग को मुक्त कराने की मांग

शहडोल।

शहडोल संभाग में पैर पसार चुके गौ तस्करी के अवैध नेटवर्क के खिलाफ कांग्रेस कौमी एकता ने सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया है। संभाग के अनूपपुर और शहडोल जिलों से लगातार हो रही मवेशियों की तस्करी से आक्रोशित कांग्रेस पदाधिकारियों ने पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक तीखा ज्ञापन सौंपा और मामले में तत्काल बड़े एक्शन की मांग की। आईजी को सौंपे ज्ञापन में कौमी एकता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सबी खान बंटी ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश से आए फिरोज उर्फ सोनू, अयूब और कादिर अली जैसे शातिर तत्व अनूपपुर के ग्राम लपटा (थाना जैतहरी) को अपना ठिकाना बनाकर स्थानीय साथियों शीतल राठौर, संजय चौधरी और एवन चौधरी के साथ मिलकर रैकेट चला रहे हैं। ये तस्कर पिकअप वाहनों के जरिए पशुओं को फुनगा, रामपुर, खाड़ा, गिरवा, जैतपुर और चुहरी के रास्तों से शहडोल के ग्राम कुदारी (थाना सीधी) पहुंचाते हैं। यहाँ से सीधी जिले के छावरी निवासी मुबारक के माध्यम से बड़े ट्रकों में लोड कर मवेशियों को सीधे उत्तर प्रदेश के उन्नाव स्थित बूचडख़ानों में भेजा जा रहा है।

रासुका के तहत हो कार्रवाई

कौमी एकता कांग्रेस ने मांग की है कि इस पूरे सिंडिकेट को ध्वस्त कर सभी आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। इस दौरान मोहसिन खान, एनएसयूआई अध्यक्ष सौरव तिवारी, मुस्कान खान, अमन तिवारी, अर्चना सिंह, नवेद आलम, महेंद्र यादव, इब्राहिम खान और ऋषभ वर्मा सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

हाई कोर्ट के आदेश बौने, उमरिया पुलिस का खेल निराला! फर्जी दस्तावेज घोटाले के आरोपियों को खाकी का खुला संरक्षण

शहडोल।

कानून के रखवाले ही अपराधियों के सामने नतमस्तक हो जाएं, तो आम जनता न्याय के लिए कहां जाए, उमरिया जिले में हुए बहुचर्चित फर्जी दस्तावेज घोटाले में कोतवाली उमरिया पुलिस की कार्यप्रणाली अब सीधे तौर पर कटघरे में है। हद तो तब हो गई जब माननीय हाई कोर्ट जबलपुर के एक नहीं, बल्कि दो-दो कड़े आदेशों को ठेंगे पर रखकर उमरिया पुलिस आरोपियों को खुला संरक्षण दे रही है। रसूखदार आरोपियों के प्रभाव में आकर पुलिस इस पूरे मामले में लीपापोती करने में जुटी है, जिससे न्याय व्यवस्था पर से जनता का भरोसा डिगने लगा है।

फर्जीवाड़ा बड़ा, लेकिन खाकी की सुस्ती उससे भी भारी

पूरा मामला ब्राइट स्टार पब्लिक स्कूल और ब्राइट फ्यूचर स्कूल (महरोई) में कूट रचित दस्तावेजों के जरिए किए गए बड़े खेल से जुड़ा है। आरोपियों ने मिलकर फर्जी अंकसूची, टी.सी. और उपस्थिति रजिस्टर तैयार कर छात्रों के नाम पर फर्जी प्रवेश दर्शाए। शिकायतकर्ता नसीम रजा खान द्वारा कोतवाली उमरिया में दर्ज कराए गए अपराध क्रमांक 0580/2024 (धारा

420, 467, 468, 470, 471, 120बी) के बावजूद महीनों बीत जाने के बाद भी पुलिस ने किसी आरोपी को जेल भेजना तो दूर, मुख्य गवाहों के बयान तक सही ढंग से दर्ज नहीं किए।

हाई कोर्ट के दो-दो आदेशों की खुलेआम अवहेलना

न्याय की आस में जब शिकायतकर्ता माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर पहुंचा, तो कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़े निर्देश जारी किए। हाई कोर्ट ने 19.12.2025 को पहला आदेश जारी कर कोतवाली उमरिया को मुख्य आरोपी शाहीन मंसूरी को तत्काल गिरफ्तार कर पूछताछ करने का हुक्म दिया था। इसके बाद कोर्ट ने 27.01.2026 को दूसरा आदेश भी दिया। लेकिन अफसोस! आज दिनांक तक कोतवाली उमरिया पुलिस ने आरोपी शाहीन मंसूरी को छूना तक मुनासिब नहीं समझा। जब पुलिस से कोर्ट के आदेश के पालन के संबंध में पूछा जाता है, तो उनका रटा-रटाया और गैर-जिम्मेदाराना जवाब आता है, जो भी कार्रवाई होगी, हम सीधे न्यायालय को बताएंगे।

फरार आरोपी घूम रहे खुलेआम

हैरानी की बात यह है कि शिकायतकर्ता नसीम रजा खान ने पुलिस महानिरीक्षक शहडोल संभाग को 22 जून को सौंपे अपने शिकायती पत्र में फरार आरोपी शाहीन मंसूरी और उसकी बहन नाहीद मंसूरी के जबलपुर स्थित ठिकानों का बकायदा पूरा पता तक सौंप दिया है। इसके बावजूद पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। आरोप है कि विवेचना अधिकारी ने जानबूझकर जिला शिक्षा विभाग के भ्रष्ट किरदारों को बचाया, अपराध स्थल का गलत नक्शा खींचा और भ्रामक पंचनामा तैयार कर मुख्य आरोपी रहीश मंसूरी को गलत फायदा पहुंचाया।

आईजी की चौखट पर न्याय की गुहार

उमरिया पुलिस की इस शर्मनाक ढिठाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ पीड़ित नसीम रजा खान ने अब पुलिस महानिरीक्षक का दरवाजा खटखटाया है। शिकायतकर्ता ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि हाई कोर्ट के दोनों आदेशों का पालन करते हुए आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी नहीं की गई, तो वे मजबूरी में न्यायहित के लिए पुनः हाई कोर्ट की शरण में अवहेलना याचिका दायर करेंगे। जनता अब पुलिस कप्तान और आईजी से सवाल पूछ रही है कि आखिर इन रसूखदार जालसाजों पर खाकी का यह विशेष कर्म कब तक जारी रहेगा?

हरिभूमि
epaper.haribhoomi.com
Jabalpur Virat Bhoomi - 25 Oct 2025 - Page 1

फर्जी दस्तावेज घोटाले में पुलिस की लीपापोती

11 माह बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे, गवाहों के बयान तक दर्ज नहीं

खबर संक्षेप

प्रतिबंध अवधि में मछली विक्रय किए जाने पर 72.26 किलोग्राम मछली जब्त

उमरिया। कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय द्वारा मछलियों के प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश नदीय मत्स्य उद्योग अधिनियम, 1972 की धारा 3(2) के अंतर्गत 16 जून 2026 से 15 अगस्त 2026 तक जिले में मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन एवं मत्स्य विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर के आदेश के पालन में 2 जुलाई को मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने उमरिया जिले के स्थानीय घुलघुली बाजार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रतिबंध अवधि में मछली विक्रय किए जाने पर कार्रवाई करते हुए 72.26 किलोग्राम मछली जब्त की गई। जब्त मछलियों को नियमानुसार नीलाम कराया गया।निरीक्षण के दौरान मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने व्यापारियों एवं आमजन को मध्यप्रदेश नदीय मत्स्य उद्योग अधिनियम, 1972 के प्रावधानों तथा मत्स्य प्रजनन काल के महत्व की जानकारी दी। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बंद ऋतु के दौरान मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन एवं मत्स्य विक्रय जैसी गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। उन्होंने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अधिनियम के तहत नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

गाली-गलौज और मारपीट का विरोध करने पर गरीब कर्मचारी को नौकरी से निकाला!

बांधवगढ़ के व्हाइट टाइगर फॉरेस्ट लॉज में सनसनी

रसूखदार लॉज प्रभारी की गुंडागर्दी

उमरिया।

विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ नेशनल पार्क के ताला स्थित मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के आलीशान व्हाइट टाइगर फॉरेस्ट लॉज के बंद कमरों और गलियारों में इन दिनों पर्यटन की नहीं, बल्कि रसूख, तानाशाही और दमन की बदबू आ रही है। रसूख के नशे में चूर लॉज प्रभारी अमित सिंह पर एक गरीब और लाचार श्रमिक को गालियां देने, जान से मारने की धमकी देने और अपने गुंडों से बेरहमी से पिटवाने का सनसनीखेज आरोप लगा है। हद तो तब हो गई जब अपनी अस्मत और हक की लड़ाई लडऩे के लिए पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक का दरवाजा खटखटाया, तो इंसाफ मिलने के बजाय पर्यटन निगम के बड़े हुक्मरानों ने रसूखदार लॉज प्रभारी का बचाव करते हुए उलटे पीड़ित श्रमिक को ही नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया।

ताला चौकी पुलिस की धमकी

मामला तब खुलकर सामने आया जब व्हाइट टाइगर फॉरेस्ट लॉज में वेटर/हाउसकीपिंग (रूम बॉय) के पद पर कार्यरत मुन्ना यादव पिता खिलाड़ी यादव, निवासी ग्राम माला, ताला ने पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती आवेदन सौंपकर लॉज प्रभारी अमित सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पीड़ित मुन्ना यादव के मुताबिक, लॉज प्रभारी अमित सिंह बिना किसी कारण के उससे हमेशा खार खाए रहते हैं। आरोप है कि अमित सिंह आए दिन मुन्ना यादव को गालियां देते हैं, जिन्हें कोई सभ्य समाज सुन तक नहीं सकता। शिकायती पत्र के अनुसार, गत 15 जून 2026 की सुबह करीब 9 बजे जब मुन्ना यादव ने इस बदसलूकी का विरोध किया और अपनी गलती पूछी, तो लॉज प्रभारी आगबबूला हो गए। उन्होंने अपनी ऊंची पहुंच का धौंस देते हुए कहा तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुमको काम से भी निकलवा दूंगा। मेरी पहुंच पुलिस से लेकर ऊपर तक है, तुम्हें आज ही नमूना दिखाता हूं। इतना ही नहीं, लॉज प्रभारी ने ताला चौकी पुलिस को फोन करके पुलिस बुलवा ली और गरीब कर्मचारी को मुकदमा बनाकर जेल में ठूंसने की सीधी धमकी दे डाली। पीड़ित का आरोप है कि अमित सिंह ने लॉज के ही कुछ अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर उसके साथ जमकर मारपीट भी करवाई।

एमपी टूरिज्म ने थमाया टर्मिनेशन लेटर

इस मामले में सबसे चौंकाने वाला और शर्मनाक मोड़ तब आया, जब पीड़ित द्वारा एसपी उमरिया से न्याय की गुहार लगाने के ठीक 15 दिन बाद, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के भोपाल स्थित मुख्यालय से एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया। प्रशासन शाखा के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा 1 जुलाई 2026 को जारी पत्र के माध्यम से मुन्ना यादव को काम की आवश्यकता न होने का बहाना बनाकर उसकी आउटसोर्सिंग एजेंसी (मेसर्स आर.बी. एसोसिएट ग्लोबल कनेक्ट प्रा.लि.) को वापस भेज दिया गया। यह सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि सरकारी तंत्र किस तरह रसूखदार अधिकारियों के काले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए पीड़ित को ही ठिकाने लगाने का काम करता है। जिस कर्मचारी ने अपनी सुरक्षा और जान-माल के खतरे को लेकर गुहार लगाई थी, उसे इंसाफ देने के बजाय पूरी तरह से बेरोजगार कर सडक़ पर ला दिया गया।

क्या रसूखदारों के आगे नतमस्तक है तंत्र

इस पूरे घटनाक्रम ने मध्य प्रदेश पर्यटन निगम और स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली को पूरी तरह सामने आ चुकी है, यदि लॉज प्रभारी अमित सिंह निर्दोष थे, तो मुन्ना यादव की शिकायत के बाद मामले की निष्पक्ष जांच क्यों नहीं कराई गई, पीड़ित द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के ठीक बाद ही पर्यटन निगम को अचानक काम की आवश्यकता खत्म होने का अहसास क्यों हुआ, क्या यह सीधे तौर पर आवाज दबाने की साजिश नहीं है। सरकारी होटलों और लॉज में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण कब बंद होगा? क्या ये कर्मचारी सिर्फ रसूखदारों की गालियां खाने और पिटने के लिए रखे गए हैं?

पीड़ित दहशत में अनहोनी की आशंका

फिलहाल पीड़ित मुन्ना यादव गहरे सदमे और दहशत में है। उसने अपने शिकायती पत्र में साफ लिखा है कि यदि भविष्य में उसके साथ कोई भी अप्रिय घटना या मारपीट होती है, तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी लॉज प्रभारी अमित सिंह और शासन-प्रशासन की होगी। अब देखना यह है कि उमरिया पुलिस और पर्यटन विभाग के आला अधिकारी इस तानाशाही पर क्या कार्रवाई करते हैं, या फिर हमेशा की तरह एक गरीब की आवाज को रसूख के पत्थरों के नीचे दबा दिया जाएगा। लोकल क्रॉनिकल इस मामले की पल-पल की अपडेट पर नजर बनाए हुए है।

कॉलेज में नव प्रवेशित छात्रों के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम संपन्न

उमरिया।

शासकीय आदर्श महाविद्यालय उमरिया में उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार तीन दिवसीयदीक्षारंभ एवं मानसिक संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन 1 जुलाई से 3 जुलाई तक किया जा रहा है । छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय की जानकारी के अंतर्गत संचालित गतिविधियों विभिन्न प्रकार की हितग्राही मूलक योजनाएं खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी के साथ मानसिक दक्षता संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य एवं तनाव प्रबंधन के लिए कार्यक्रमों का आयोजन महाविद्यालय प्राचार्य डॉ नियाज अहमद अंसारी की अध्यक्षता, प्रवेश प्रभारी डॉ.विजय डाबर के संयोजन एवं डॉ राजीव तिवारी के संचालन में किया गया। कार्यक्रम के प्रथम दिवस 1 जुलाई 2026 को छात्र-छात्राओं का पुष्प वर्षा एवं तिलक वंदन के साथ स्वागत अभिनंदन किया गया । कार्यक्रम में डॉ अतुल बाजपेई प्राचार्य शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय एवं हार्टफुलनेस प्रशिक्षक सुश्री प्रणाली पांसे की उपस्थिति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे । महाविद्यालय का परिचय डॉ परमेश्वर सिंह मरावी ,राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी रेम सिंह हितग्राही मूलक योजनाओं

को शिव हल्दकार एवं विषय पाठ्यक्रम की जानकारी डॉ नवीन उपाध्याय द्वारा प्रदान की गई।
कार्यक्रम के द्वितीय दिवस छात्र-छात्राओं को साइबर क्राइम एवं साइबर सुरक्षा सडक़ प्रबंध सडक़ सुरक्षा आदि से संबंधित जानकारी पुलिस अधीक्षक विजय कुमार भगवानी एवं ट्रैफिक विभाग की ज्योति शुक्ला सहित श्री मरावी की उपस्थिति में छात्र छात्राओं को जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रमों के आयोजन में महाविद्यालय के समस्त शिक्षक अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति रही। महाविद्यालय स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना,भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ एवं क्रीड़ा विभाग के संयुक्त आयोजन में किया जा रहा है ।

भौगोलिक स्थिति अनुसार बनेगी कार्य योजना: जिला पंचायत अध्यक्ष

योजना के संचालन से ग्राम पंचायतें होगी सुदृढ़: कलेक्टर ग्रामीण रोजगार की गारंटी विकसित भारत जी राम जी का ग्राम पठारी से हुआ शुभारंभ

उमरिया। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और लोगों की आजीविका को सशक्त बनाने के उद्देश्य से विकसित भारत जी-राम-जी एक्ट के अंतर्गत 125 दिनों के रोजगार की गारंटी का प्रावधान किया गया है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को अधिक समय तक रोजगार उपलब्ध कराना, उनकी आय में वृद्धि करना तथा गांवों के समग्र विकास को गति देना है। उक्त आशय के विचार जिला पंचायत अध्यक्ष अनुजा पटेल ने ग्राम पंचायत पठारी में आयोजित ग्रामीण रोजगार की गारंटी विकसित भारत जी राम जी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि योजना के तहत भौगोलिक स्थिति अनुसार कार्य योजनाएं बनेगी, जिसका सीधा लाभ ग्रामीणों को मिलेगा। उन्होने कहा कि योजना के तहत प्राप्त प्रशिक्षण अनुसार ग्राम पंचायतें कार्य योजना तैयार करें और योजना को सफल बनाएं। जी राम जी योजना का उद्देश्य हर पात्र व्यक्ति को लाभ दिलाना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय ने कहा कि मनरेगा योजना का अपडेट कर जी राम जी में परिवर्तित किया गया है। यह योजना ग्रामीणों के लिए मील

का पत्थर साबित होगी।
उन्होने बताया कि योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को और अधिक सुदृढ़ करना है। योजना के तहत ग्राम पंचायतों को अब स्वयं निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होगी। जीरामजी योजना का से काम का दायरा बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि योजना के माध्यम से पात्र ग्रामीण परिवारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उन्हें रोजगार की तलाश में पलायन नहीं करना पड़े। रोजगार के दौरान जल संरक्षण, वृक्षारोपण, सडक़ निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार, स्वच्छता, भूमि विकास तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग के विकास कार्य कराए जाएंगे। इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी सुनिश्चित होगा।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह ने कहा कि ग्रामीण रोजगार की गारंटी विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत अब 125 दिनों की रोजगार गारंटी से गरीब एवं श्रमिक परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तथा महिलाओं की कार्य भागीदारी भी बढ़ेगी।
योजना का उद्देश्य पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध तरीके से रोजगार उपलब्ध कराना है ताकि प्रत्येक पात्र परिवार को इसका लाभ मिल सके।
यह पहल आत्मनिर्भर गांव, मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी और प्रभावी क्रियान्वयन से यह योजना रोजगार सृजन के साथ-साथ टिकाऊ

जेबीसीसीआई-12 के गठन की मांग को लेकर संयुक्त मोर्चा का शक्ति प्रदर्शन

सैकड़ों श्रमिकों ने जीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन

हरिभूमि न्यूज बदरा/जमुना।

12वें वेतन समझौते को लेकर कोयला श्रमिक संगठनों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। बुधवार को मांग दिवस के अवसर पर जमुना-कोतमा क्षेत्र में संयुक्त मोर्चा के बैनर तले महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष सैकड़ों श्रमिकों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए जेबीसीसीआई-12 के तत्काल गठन की मांग उठाई। गगनभेदी नारों के बीच आयोजित इस प्रदर्शन में लगभग 200 से अधिक श्रमिक शामिल हुए, जिनमें बड़ी संख्या में महिला श्रमिकों की उपस्थिति भी आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम का संचालन रमाशंकर तिवारी ने किया। उन्होंने उपस्थित श्रमिकों का स्वागत करते हुए कहा कि 12वें वेतन समझौते के लिए यदि लंबा संघर्ष करना पड़े तो सभी श्रमिकों को एकजुट होकर नई ऊर्जा के साथ आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने श्रमिकों से किसी भी प्रकार के भ्रम या भटकावे से बचते हुए संयुक्त मोर्चा का मजबूती से साथ देने का आहवान किया। सभा को संबोधित करते हुए एचएमएस के कौशलाधीश द्विवेदी, इंटक के संजय पटेल, एटक के अयाज अली तथा सीटू के इंद्रपति सिंह ने कहा कि कोयला श्रमिक लंबे समय से 12वें वेतन समझौते की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब तक जेबीसीसीआई-12 का गठन नहीं किया गया है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि श्रमिक हितों की अनदेखी की जा रही है तथा कुछ संगठन सरकार के पक्ष में खड़े होकर श्रमिकों के हितों से समझौता कर रहे हैं। उन्होंने श्रमिकों से ऐसे प्रयासों के प्रति सतर्क रहने और संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन को मजबूत करने की अपील की। वक्ताओं ने कहा कि यदि जल्द ही जेबीसीसीआई-12 का गठन कर वेतन समझौते की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो संयुक्त मोर्चा चरणबद्ध आंदोलन को और तेज करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी कोल इंडिया प्रबंधन एवं केंद्र सरकार की होगी। प्रदर्शन के दौरान मोहन पांव, अनिल शर्मा, रमेश कुशवाहा, ऋषिनारायण तिवारी, शरद त्रिवेदी, रवि त्रिवेदी, शारदा सिंह, उत्तम तिवारी, अमन कुमार, शंभु शरण राय, के.के. पांडेय, प्रमोद खंडईया, बिक्रम प्रसाद, सुनील तिवारी, वाल्मीकि मिश्रा सहित संयुक्त मोर्चा के अनेक पदाधिकारी एवं सैकड़ों श्रमिक उपस्थित रहे। सभा के समापन पर श्रमिकों ने इंकलाब जिंदाबाद और मजदूर एकता जिंदाबाद के नारों के साथ जमुना-कोतमा क्षेत्र के पर्सनल विभाग के माध्यम से कोल इंडिया के अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जेबीसीसीआई-12 का तत्काल गठन कर 12वें वेतन समझौते की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई। संयुक्त मोर्चा ने स्पष्ट किया कि मांगें पूरी नहीं होने की स्थिति में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

कोतमा में ऑटो चालकों की मनमानी से यात्री परेशान, किराया निर्धारण की मांग तेज

हरिभूमि न्यूज कोतमा।

नगर में ऑटो और ई-रिक्शा चालकों की मनमानी से आम नागरिक परेशान हैं। प्रशासन की ओर से अब तक किराया तय नहीं किए जाने का लाभ उठाकर चालक यात्रियों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। हालात यह हैं कि कम दूरी के सफर के लिए भी कई बार 100 से 150 रुपये तक किराया मांग लिया जाता है। विरोध करने पर यात्रियों और चालकों के बीच विवाद की स्थिति भी बन जाती है। नगर में बस स्टैंड, बाजार, टैक्सी स्टैंड, भालूमाड़ा, जमुना, गोविंदा, लहसुई कैंप कॉलोनी और रेलवे स्टेशन सहित विभिन्न मार्गों पर बड़ी संख्या में ऑटो एवं ई-रिक्शा संचालित हो रहे हैं। इन मार्गों पर प्रतिदिन सैकड़ों लोग सफर करते हैं, लेकिन किसी भी रूट का अधिकृत किराया निर्धारित नहीं होने से चालक अपनी सुविधा अनुसार किराया तय कर रहे हैं। रात के समय और महिला यात्रियों से अधिक किराया वसूलने की शिकायतें भी सामने आती रहती हैं। नगर में ऑटो और ई-रिक्शा में यात्रियों की संख्या को लेकर भी कोई प्रभावी नियंत्रण नजर नहीं आता। कई वाहन क्षमता से अधिक सवारियां बैठाकर संचालित किए जा रहे हैं। इससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ने के साथ ही महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। यातायात नियमों और सुरक्षा मानकों की अनदेखी लगातार जारी है। जानकारी के अनुसार, पूर्व में जिला मुख्यालय अनूपपुर में परिवहन विभाग ने ऑटो चालकों की बैठक लेकर विभिन्न रूटों का किराया निर्धारित किया था तथा प्रत्येक ऑटो में किराया सूची भी चस्पा कराई गई थी। इससे यात्रियों को सुविधा मिली और अनावश्यक विवाद भी कम हुए। स्थानीय नागरिकों ने जिला परिवहन एवं यातायात विभाग से मांग की है कि कोतमा सहित अन्य तहसील मुख्यालयों में भी ऑटो चालकों की बैठक आयोजित कर सभी रूटों का किराया निर्धारित किया जाए। साथ ही प्रत्येक ऑटो और ई-रिक्शा में किराया सूची अनिवार्य रूप से चस्पा कराई जाए तथा समय-समय पर इसकी निगरानी भी की जाए। नागरिकों का कहना है कि वर्तमान में बस स्टैंड से तहसील, गोविंदा, लहसुई कैंप कॉलोनी या बाजार जैसे कम दूरी के मार्गों पर भी कई चालक 150 रुपये तक किराया मांगते हैं। इससे आम लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

दिन में जल रही स्ट्रीट लाइटें, बिजली की बर्बादी पर उठे सवाल

हरिभूमि न्यूज कोतमा। नगर में दिन के समय भी स्ट्रीट लाइटों का लगातार जलना लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। नागरिकों का कहना है कि यह न केवल बिजली की अनावश्यक बर्बादी है, बल्कि जनता के टैक्स के पैसे का भी दुरुपयोग है। लोगों ने नगर पालिका से इस समस्या पर तत्काल ध्यान देने की मांग की है। स्थानीय लोगों के अनुसार नगर के कई क्षेत्रों में सुबह होने के बाद भी घंटों तक स्ट्रीट लाइटें जलती रहती हैं। इससे बिजली की खपत बढ़ने के साथ विद्युत व्यवस्था पर भी अनावश्यक बोझ पड़ता है। नागरिकों का कहना है कि यदि समय पर इन लाइटों को बंद किया जाए तो बिजली की बचत के साथ नगर पालिका के खर्च में भी कमी आ सकती है। जानकारों के अनुसार अधिकांश स्थानों पर स्ट्रीट लाइटों में लगे ऑटोमैटिक सेंसर या टाइमर खराब होने के कारण यह समस्या उत्पन्न होती है। सेंसर खराब होने पर लाइटें दिन में भी स्वतः बंद नहीं हो पातीं, जिससे घंटों तक बिजली की बर्बादी होती रहती है। नागरिकों का आरोप है कि नगर पालिका द्वारा स्ट्रीट लाइट व्यवस्था की नियमित निगरानी और खराब सेंसरों की समय पर मरम्मत नहीं कराई जा रही है। यदि समय-समय पर निरीक्षण और रखरखाव किया जाए तो इस समस्या से आसानी से निजात मिल सकती है। लोगों ने नगर पालिका प्रशासन से मांग की है कि खराब सेंसर एवं टाइमर की तत्काल जांच कर उन्हें दुरुस्त कराया जाए, ताकि बिजली की अनावश्यक बर्बादी रोकी जा सके और सार्वजनिक धन का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो।

धूल से परेशान लोगों ने लगाए पर्यावरण मानकों की अनदेखी के आरोप

राजनगर रोड सेल यार्ड में प्रदूषण नियंत्रण पर उठे सवाल

हरिभूमि न्यूज बदरा/जमुना।

एसईसीएल हसदेव क्षेत्र के राजनगर रोड सेल स्टॉक यार्ड में पर्यावरण मानकों के पालन को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। नागरिकों का आरोप है कि यार्ड से उड़ने वाली कोयले की धूल के कारण आसपास की बस्तियों में रहने वाले लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोगों का कहना है कि ग्रीन माइनिंग और प्रदूषण नियंत्रण के दावे जमीनी स्तर पर पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहे हैं। स्थानीय नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि यार्ड की सीमा पर प्रभावी विंड ब्रेकर दीवारें और पर्याप्त थ्री-टियर ग्रीन बेल्ट विकसित नहीं की गई है। उनका कहना है कि तेज हवा और कोयले की लोडिंग-अनलोडिंग के दौरान उठने वाली धूल सीधे रिहायशी क्षेत्रों तक पहुंच रही है। कई घरों की छतों, आंगनों तथा आसपास के क्षेत्र में कोयले की धूल जमा होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। लोगों का यह भी कहना है कि कोल इंडिया की पर्यावरण संबंधी

गाइडलाइन के अनुसार कोयले के ढेरों पर नियमित पानी का छिड़काव, फॉग कैनन, पक्के आंतरिक मार्ग तथा धूल नियंत्रण के अन्य उपाय प्रभावी ढंग से लागू होने चाहिए। आरोप है कि कई स्थानों पर इन व्यवस्थाओं का अपेक्षित स्तर पर पालन नहीं हो रहा, जिससे धूल का गुबार लगातार फैल रहा है। परिवहन व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई कोयला परिवहन वाहनों में तिरपाल ठीक से नहीं लगाया जाता और व्हील वॉश जैसी व्यवस्था भी प्रभावी नहीं दिखती। इसके कारण मुख्य मार्गों पर कोयले की धूल फैल रही है, जिससे राहगीरों, स्कूली बच्चों और स्थानीय दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकों ने मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर पर्यावरण मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि आवश्यक व्यवस्थाओं में कमी पाई जाती है तो उन्हें तत्काल दुरुस्त कराया जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को प्रदूषण से राहत मिल सके।

इनका कहना है

पूरे क्षेत्र में नियमित पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। पर्यावरण की गाइडलाइन के अनुसार सभी आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं। यदि राजनगर रोड सेल स्टॉक यार्ड में कहीं भी पर्यावरण मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है तो आप हमें बताइए। हम संबंधित ठेकेदार को और सख्ती से निर्देश देंगे तथा व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे।

जिंदल रजक, पर्यावरण अधिकारी
राजनगर हसदेव क्षेत्र

खबर संक्षेप

सुमित गुर्जर के स्थानांतरण के बाद नहीं आया कोई तहसीलदार जनता हो रही परेशान

ब्यौहारी। तहसील कार्यालय व्यवहारी में इन दोनों व्यावहारी सर्कल एवं ऑखेटपुर सर्कल खाली है कारण यह है कि यहां पर पदस्थ तहसीलदार सुमित गुर्जर ने अपना बैतूल ट्रांसफर करा लिया है लेकिन कलेक्टर द्वारा उनको रिलीव नहीं किया गया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रिलीव नहीं होने के बावजूद वह काम नहीं कर रहे हैं उनका परिवार बुढ़ार में रहता है वहीं रह रहे और जल्द से जल्द यहां से रिलीव होना चाहते हैं उनके कार्य नहीं करने के कारण तहसील कार्यालय खाली है कोई काम नहीं हो पा रहा उल्लेखनीय है कि पूर्व में पदस्थ राजकुमार कोल को यहां से हटा दिया गया था उनकी जगह सुमित गुर्जर को यहां भेजा गया उन्होंने भी अपना स्थानांतरण अपने गृह ग्राम के पास बैतूल करा लिया अभी ब्यौहारी- में दो नायब तहसीलदार हैं जिसमें अजय पांडे जिनके पास पपौध और बांणसागर का प्रभार है अंकिता पांडे जिनके पास बुड़बा सर्किल है लेकिन व्यवहारी और आंखेंटपुर सर्किल खाली है यहां से सनी द्विवेदी को जैसिंनगर भेज दिया गया राजकुमार कोल भी जो तहसीलदार बनकर आए थे वह नायब तहसीलदार हैं उनको प्रभारी तहसीलदार बनाकर भेजा गया था यदि राजकुमार कोल को प्रभारी तहसीलदार बनाकर भेजा जा सकता है तो यदि शनि द्विवेदी को प्रभारी तहसीलदार बनाकर जैसीनगर से ब्यौहारी- भेज दिया जाए तो व्यवस्था बन जाएगी और राजकुमार कोल को सनी द्विवेदी के जगह में जयसिंहनगर भेज दिया जाए इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी क्योंकि अभी वह शहडोल में है और उनके पास किसी भी तहसील का प्रभार भी नहीं है
अब देखना यह है कि कलेक्टर कब तक ब्यौहारी- में तहसीलदार भेजते हैं जब तक तहसीलदार नहीं आ जाते तब तक जनता की परेशानी बढ़ना तय ही है।

दीक्षारंभ समारोह में नवप्रवेशित विद्यार्थियों का महाविद्यालय ने किया स्वागत

उमरिया। प्रदेश शासन के निर्देशानुसारदीक्षारंभ समारोहका आयोजन महाविद्यालय में दिनांक 01 जुलाई 2026 को किया गया। महाविद्यालय में नवप्रवेशित विद्यार्थियों का स्वागत समारोह आयोजित कर इस अवसर पर विद्यार्थियों का तिलक कर एवं पेन भेंट कर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में आत्मीयता एवं अध्ययन के प्रति प्रेरणा जागृत करना रहा। महाविद्यालय परिवार ने इस परंपरागत स्वागत से विद्यार्थियों को शिक्षा यात्रा के लिए शुभकामनाएं दीं और उन्हें अनुशासन, परिश्रम तथा समर्पण की भावना के साथ आगे बढने का संदेश दिया।कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्यडॉ. विमला मरावीने की।समारोह में नवप्रवेशित विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यार्थियों को संस्थान की स्थापना, उपलब्धियों, शैक्षणिक गतिविधियों, नियमों एवं सुविधाओं की जानकारी दी गई। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, बहुविषयक शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगारोन्मुखी अवसरों पर विशेष सत्र आयोजित किए गए।
एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अरविंद शाह बरकड़ेने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों को सामाजिक उत्तरदायित्व, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, नशामुक्ति एवं मतदान जागरूकता से जुडने का आह्वान किया।

बाबा बर्फानी के दरबार को निकला आस्था का कारवां, 'हर-हर महादेव' के जयघोष से गूंजा धनपुरी

माल्यार्पण, चंदन-तिलक और ढोल-नगाड़ों के बीच अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को दी गई भावभीनी विदाई, 10-12 वर्षों से लगातार यात्रा कर रहे कई श्रद्धालु

धनपुरी। सावन की आहट के साथ शिवभक्ति का रंग पूरे क्षेत्र में गहराने लगा है। इसी कड़ी में गुरुवार को धनपुरी से पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था भक्ति, उत्साह और उल्लास के बीच रवाना हुआ। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकले श्रद्धालुओं की विदाई किसी धार्मिक उत्सव से कम नहीं थी। नगर में जगह-जगह श्रद्धालुओं का माल्यार्पण किया गया, चंदन-तिलक लगाकर उनका अभिनंदन किया गया और ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच 'हर-हर महादेव', 'बम-बम भोले' तथा 'जय बाबा बर्फानी' के जयघोष से पूरा वातावरण शिवमय हो उठा।

यात्रा पर रवाना होने वाले श्रद्धालुओं के चेहरों पर बाबा के दर्शन की उत्कंठा साफ दिखाई दे रही थी। परिजन और मित्र जहां एक ओर उन्हें शुभकामनाओं के साथ विदा कर रहे थे, वहीं श्रद्धालु भगवान शिव का स्मरण करते हुए बाबा बर्फानी के पवित्र धाम की ओर प्रस्थान कर रहे थे। पूरे आयोजन के दौरान आस्था, श्रद्धा और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिला।इस वर्ष भी यात्रा दल में ऐसे अनेक शिवभक्त शामिल हैं, जो पिछले 10 से 12 वर्षों से लगातार अमरनाथ यात्रा कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि बाबा भोलेनाथ की असीम कृपा और आशीर्वाद से ही उन्हें हर वर्ष इस कठिन एवं पावन यात्रा का अवसर मिलता है। उनका विश्वास है कि बाबा के दर्शन से जीवन में नई ऊर्जा, आत्मिक शांति और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
यात्रा पर रवाना होने वालों में नारायण बहादुर शर्मा, पंकज शर्मा, आशीष सिंह, बृजेश शुक्ला, राजेश सोनी, मुकेश चौकसे, श्रावण शुक्ला, रजत कुमार पांडेय, दीप नारायण, दुर्गेश, नरेंद्र तिवारी, पुष्पेंद्र नारायण तिवारी, नागेंद्र तिवारी, आशुतोष एवं एस.पी. सिंह प्रमुख रूप से शामिल रहे। श्रद्धालुओं को विदा करने के लिए नगर के गणमान्य नागरिकों और शिवभक्तों की बड़ी संख्या उपस्थित रही। अधिवक्ता संघ बुढ़ार के अध्यक्ष जयकांत मिश्रा, पूर्व सीएमओ रविकांत त्रिपाठी, मनोज जैन, राकेश तिवारी, रवि सिंह कश्यप, पूरन लोधी, हीरालाल विश्वकर्मा, जनक कुशवाहा, सी.पी. सिंह, मानसी चौकसे, पार्षद खुशी, सुकृति सिंह, शुभम जैन, ऋषि जैन सहित अनेक लोगों ने श्रद्धालुओं का पुष्पमालाओं से स्वागत कर मंगलमय यात्रा की कामना की। धार्मिक उल्लास से सराबोर इस अवसर पर नगरवासियों ने बाबा अमरनाथ से क्षेत्र में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। सभी ने कामना की कि बाबा बर्फानी की कृपा से यात्रा पूरी तरह सुरक्षित एवं सफल रहे तथा सभी श्रद्धालु सकुशल लौटकर पुनः अपने परिवार और समाज के बीच पहुंचें। धनपुरी से रवाना हुआ यह पहला जत्था केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि सनातन आस्था, अटूट विश्वास और सामाजिक एकजुटता का जीवंत प्रतीक बन गया।

अमृत स्टेशन योजनाः शहडोल, उमरिया और अनूपपुर रेलवे स्टेशनों की बदलेगी सूरत, CPM राजीव कुमार और Sr. DEN अरविंद विश्वकर्मा हुए सम्मानित

शहडोल। भारतीय रेल अब एक नए और आधुनिक दौर में प्रवेश कर चुका है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन विकास योजना के तहत शहडोल, उमरिया और अनूपपुर रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। स्टेशनों की पुरानी और संकरी व्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए अब यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं देने की तैयारी पूरी हो चुकी है।
अत्याधुनिक सर्कुलेटिंग एरिया और इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माणयोजना के अंतर्गत स्टेशनों के सर्कुलेटिंग एरिया को पूरी तरह आधुनिक रूप दिया गया है।
अब यात्रियों को यहाँ निम्नलिखित सुविधाएं मिलेंगीःचौड़ी सड़कें और रिंग रोडः यात्रियों के सुगम आवागमन के लिए चौड़ी सड़कों के साथ-साथ एक विशेष रिंग रोड का निर्माण किया गया है।आधुनिक लाइटिंग व पार्किंगः पूरे परिसर को आधुनिक लाइटों से रोशन किया गया है, साथ ही विभिन्न वाहनों के लिए बड़े और सुविधाजनक पार्किंग स्पेस बनाए गए हैं।
नया निर्माणः विकास कार्य के दौरान हटाए गए पुराने पार्क, रेलवे आवास और कार्यालयों के बदले रेलवे कॉलोनी में नवीन पार्क, नए रेलवे आवास और अत्याधुनिक कार्यालयों का निर्माण किया गया है।
नए विज़न से कार्यों में आई तेजीविभागीय सूत्रों के अनुसार, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर (CPM) राजीव कुमार के पदभार ग्रहण करते ही अमृत स्टेशन विकास योजना के कार्यों में अभूतपूर्व तेजी आई है।द्वितीय चरण की योजनाः आगामी दूसरे चरण में पुरानी स्टेशन बिल्डिंग के स्थान पर कमर्शियल रिक्वायरमेंट (व्यावसायिक आवश्यकताओं) के हिसाब से नई गगनचुंबी बिल्डिंग बनाई जाएगी। इसमें आधुनिक मॉल, लाउंज, दुकानें और विश्राम

गृह (रेस्ट हाउस) शामिल होंगे। साथ ही सक्षम अधिकारियों की अनुमति से सर्कुलेटिंग एरिया में सुलभ शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा।
उत्कृष्ट कार्यों के लिए अधिकारियों का सम्मानरेलवे के इस बदलते स्वरूप और शानदार कार्यप्रणाली को देखते हुए साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे (SECR) मजदूर कांग्रेस बिलासपुर द्वारा अधिकारियों की सराहना की गई है।01 जुलाई को वरिष्ठ मंडल अभियंता (समन्वयक) बिलासपुर अरविंद विश्वकर्मा के चेंबर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए CPM राजीव कुमार एवं Sr. DEN (समन्वयक) अरविंद विश्वकर्मा को रेलवे मजदूर कांग्रेस बिलासपुर मंडल की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर संगठन के मंडल समन्वयक विजय अग्निहोत्री, जोनल कार्यकारी सीआईसी प्रभारी अध्यक्ष लक्ष्मण राव, अतिरिक्त संयुक्त महामंत्री शुभम उपाध्याय और रायगढ़ शाखा सचिव संजय श्रीवास्तव मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

जल गंगा संवर्धन अभियान बना जन जन का अभियान

ब्यौहारी। विकासखंड व्यवहारी के प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल चिपाडनाथ धाम में आज दिनांक 30 जून को जल गंगा संवर्धन अभियान के तृतीय चरण बाबडी उत्सव के कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि के रूप में व्यवहारी विधानसभा के विधायक शरद जुगलाल कोल ने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के मनसा अनुसार पूरे देश और मध्य प्रदेश में विगत 3 महीने से जल गंगा संवर्धन अभियान जन-जन का अभियान बन गया जिसके तहत बड़े स्तर पर गांव-गांव तक तालाबों की स्वच्छता हैंड पंपों के पास सोख्ता निर्माण कंट्रोल ट्रेंच एवं जल स्त्रोतों की सफाई का कार्य किया गया आगे आने वाले वर्षा के पानी को रोकने तथा रिचार्ज होने के लिए पर्याप्त प्रयास हुए निश्चित ही इस कार्य का सुखद परिणाम हमें आगे मिलेगा कार्यक्रम में जनपद पंचायत की अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत व्यवहारी उपस्थित रहे बावड़ी उत्सव के कार्यक्रम में जल स्त्रोत का पूजन करने के उपरांत चिपाडनाथ प्रांगण में पांच पौधों का रोपन किया गया तथा स्वच्छता अभियान चलाकर परिसर को साफ सुथरा रखने की प्रेरणा दी गई कार्यक्रम का संचालन शिवदत्त उरमलिया मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के द्वारा किया गया कार्यक्रम में नवांकुर संस्था के प्रतिनिधियों को मेडल से सम्मानित करने के साथ ही आगे भी इसी प्रकार के कार्य चलते रहें उत्साह वर्धन किया गया उपरोक्त कार्यक्रम में इंजीनियर नोखे लाल गुप्ता पंचायत के ग्राम पंचायत मऊ के सरपंच जानकी राठौर , समाजसेवी द्वारिका राठौर, भमरहा सरपंच आरती गुप्ता, राम लखन गुप्ता, सुखेंद्र गुप्ता अध्यक्ष नवांकुर समिति, कई ग्राम पंचायतों के सचिव सरपंच रोजगार सहायक ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियों के अध्यक्ष सचिव एवं नवांकुर संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे

घर घर पहुंच कर पिलाई गई पोलियो की खुराक

ब्यौहारी। प्रदेशव्यापी अभियान के तहत 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से मुक्ति के लिए पोलियो की खुराक पिलाई गई सीबीएमओ डॉ निशांत सिंह परिहार के निर्देशन में प्रमुख स्थान पर पोलियो की खुराक पिलाने के लिए आशा एवं एएनएम को तैनात किया गया और जो बच्चे नहीं पहुंच सकते उनके लिए नगर के हर वार्ड में मोबाइल टीम ने घर-घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गांव गांव में आशा कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य अमला पहुंच करके 29 और 30 जून को पोलियो की खुराक पिलाई गई बीसीएम राम कल्याण बैश ने कहा कि यह अमृत की बूंद है जिससे कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए कोई भी बच्चा है यदि पोलियो से ग्रसित हो जाता है तो उसका पूरा जीवन बेकार हो जाता है और हमेशा के लिए माता-पिता पर बोझ बन जाता है इसलिए हर एक माता-पिता को स्वयं सजग होकर जीरो से 5 साल तक के जब भी शासन के निर्देश जारी होते हैं प्रत्येक काम छोड़कर के पोलियो की खुराक पिलानी चाहिए।

बजबजाती नाली, टूटी सड़क और खुले ढक्कन... वार्ड 17/15 के रहवासी नारकीय जीवन जीने को मजबूर

पुराने बैंक ऑफ बड़ौदा के पीछे की गली में वर्षों से नहीं हुई सफाई, बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें; मच्छरों और हादसों का खतरा

धनपुरी। नगर पालिका की सफाई व्यवस्था के दावों की पोल वार्ड क्रमांक 17/15 स्थित पुराने बैंक ऑफ बड़ौदा के पीछे की गली खोल रही है। यहां वर्षों से नाली की समुचित सफाई नहीं होने के कारण पूरी नाली गंदगी, कचरे और कीचड़ से अटी पड़ी है। बरसात के दिनों में स्थिति और भी भयावह हो गई है। नाली का गंदा पानी जगह-जगह जमा होकर बदबू फैला रहा है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों का जीवन दूभर हो गया है।
सबसे चिंताजनक बात यह है कि नाली के ऊपर लगाए गए कंक्रीट के ढक्कन कई स्थानों पर टूट चुके हैं, जबकि कई हिस्सों में नाली पूरी तरह खुली हुई है। इससे हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। विशेषकर रात के समय और बारिश के दौरान दोपहिया वाहन चालकों, बच्चों तथा बुजुर्गों के लिए यह गली किसी खतरे से कम नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार कई वाहन चालक संतुलन बिगड़ने से गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं।
गली की सड़क भी पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। जगह-जगह गड्ढे बन गए हैं और बारिश का पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा तक नहीं लग पाता। लोगों को रोजाना कीचड़ और जलभराव के बीच आवागमन करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि लंबे समय से नाली की सफाई नहीं होने के कारण मच्छरों

का प्रकोप तेजी से बढ़ गया है। गंदगी और दूषित वातावरण के कारण डेंगू, मलेरिया तथा अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। लोगों का आरोप है कि कई बार संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की गई, लेकिन समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है।
क्षेत्रवासियों का कहना है कि नगर पालिका केवल कागजों में सफाई अभियान चलाती दिखाई देती है, जबकि धरातल पर हालात बेहद खराब हैं। लोगों ने मांग की है कि तत्काल विशेष सफाई अभियान चलाकर नाली की पूरी तरह सफाई कराई जाए, टूटे हुए ढक्कनों को बदला जाए, जर्जर सड़क की मरम्मत कराई जाए और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।बरसात के इस मौसम में यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो गंदगी, जलभराव और मच्छरों के कारण क्षेत्र में संक्रामक बीमारियां फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखना यह होगा कि नगर पालिका प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कब तक ध्यान देता है या फिर वार्डवासी इसी तरह नारकीय परिस्थितियों में जीवन जीने को मजबूर रहेंगे।

कलेक्टर ने घुलघुली विद्यालय का किया निरीक्षण एवं ग्रामीणों से किया संवाद

विस्थापन की कार्यवाही में ग्रामीणों से सहयोग करनें की अपील की

उमरिया। कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय कि अध्यक्षता में ग्राम पंचायत घुलघुटी के शासकीय उमा वि शाला में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बताया गया कि कंचन विस्तार परियोजना कंचनपुर ओपन माइंस द्वारा कोयला उत्खनन करने के दौरान आस पास के रहवास पर कंपन उत्पन्न होती है। ग्रामीणों की जान माल की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम से ग्रामीणों के विस्थापन की कार्यवाही की जानी है ।
कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय ने कहा कि ग्राम में स्थित शासकीय उच्च माध्यमिक शाला के समीप कॉलरी आ चुकी है जिससे ब्लास्टिंग के दौरान भवन में कम्पन होता है जिससे भवन क्षतिग्रस्त होने से बच्चों के जान को खतरा के दृष्टिगत बच्चों को अध्ययन हेतु घुलघुली से लगभग 1-2 कि.मी. दूर कक्षा 6 वीं से 8 तक के बच्चों को शासकीय प्राथमिक शाला नरवार-29 में तथा कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को घुलघुली से लगभग 6-7 कि.मी. दूर शा0 उ मा वि विद्यालय जरहा में शिफ्ट करने की कार्यवाही की जाएगी। घुलघुली से उक्त जरहा स्कूल तक बच्चों के आवागमन हेतु एसईसीएल को वाहन व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिये गये हैं।
उन्होंने ग्रामीणों का आव्हान करते हुए बताया कि ग्राम गहिराटोला में स्कूल निर्माण हेतु जमीन आवंटन किया गया है एवं नई स्कूल बिल्डिंग जल्द ही बनायी जाएगी, लेकिन जब तक नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा न हो जाए, तब तक अपनें बच्चों को उक्त स्कूलों में भेजें ताकि उनके अध्यापन के कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो सके। बैठक में एसईसीएल व्दारा बताया गया कि ग्राम में 235 घरों के सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है एवं 15 घरों के सर्वे का कार्य होना बांकी है। कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय ने कहा कि ग्रामीण जन किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, शासन व्दारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए ग्रामीणों की समस्याओं का निदान किया जाएगा तथा एस ई सी एल के उपस्थित अधिकारियों जल्द सर्वे कार्य पूर्ण करने व शासन के मुआवजा से संबंधित नियमों की कांपी समस्त परिवारों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये ताकि सभी कार्यवाही पारदर्शी रूप से किया जा सके। इस दौरान उन्होने शासकीय प्राथमिक नरवार-29 एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जरहा का भी अवलोकन किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान उन्होने एसईसीएल को जरहा स्कूल में बायो टॉयलेट स्थापित करनें के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के समय सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह, एसडीएम बांधवगढ़ अम्बिकेश प्रताप सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी, सरपंच बीआरसी एवं एसईसीएल के अधिकारी सहित ग्रामीण जन उपस्थित रहे।

एसडीओपी मुकेश अविंद्रा की हुई विदाई

ब्यौहारी। व्यवहारी के एसडीओपी मुकेश अविंद्रा अपनी अधिवर्षकी की पूरा करके व्यवहारी से रिटायर हो गये उनका भव्य विदाई समारोह आयोजित किया गया कार्यक्रम के मुख्य विधायक शरद कोल एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में ऋषभ छारी डीएसपी मौजूद रहे विदाई समारोह में एसडीओपी का पूरा परिवार पुत्र एवं पुत्र बधू एवं उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद थी उनका कार्यकाल व्यवहारी में अविवादित रहा और उन्होंने बड़े से बड़े विवाद को भी बहुत ही सरल ढंग से सुलझा लिया कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर निरीक्षक जिया उल हक द्वारा की गई सोहागपुर जयसिंहनगर, सीधी बाणसागर ,पपौंध थाना प्रभारी, विशिष्ट जन एवं ब्यौहारी थाना के समस्त स्टॉफ मौजूद रहा। सभी ने एसडीओपी के आगे के जीवन के स्वस्थ जीवन की है।

भगवान जगन्नाथ रथयात्रा 16 जुलाई को,रूपरेखा तय करने आज श्री राम जानकी मंदिर में होगी बैठक

बुढार। क्षेत्र के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री राम जानकी मंदिर,में इस वर्ष भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथयात्रा को अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आगामी 16 जुलाई 2026, दिन गुरुवार को निकलने वाली इस भव्य रथयात्रा के सुचारू संचालन और इसकी भव्यता को और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया है।
श्री राम जानकी मंदिर के महंत श्री अर्जुन दास जी महाराज ने क्षेत्र के सभी धर्मप्रेमियों, माताओं, बहनों और ऊर्जावान युवाओं से इस बैठक में शामिल होने का भावपूर्ण आग्रह किया है। 3 जुलाई 2026 (दिन शुक्रवार को शाम 4:00 बज,श्री राम जानकी मंदिर, बुढार।महंत श्री अर्जुन दास जी महाराज का संदेशःप्रिय भक्तों, जय जगन्नाथ! इस वर्ष श्री राम जानकी मंदिर से निकलने वाली भगवान जगन्नाथ जी की रथयात्रा को और अधिक भव्य व दिव्य कैसे बनाया जाए, इसी पावन उद्देश्य से यह बैठक बुलाई गई है। रथयात्रा के कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने के लिए आप सभी धर्मप्रेमी अपने इष्ट-मित्रों सहित इस बैठक में अवश्य पधारें और अपने बहुमूल्य सुझाव साझा करें।

खबर संक्षेप

वर्षा ऋतु में पशुओं को संक्रामक बीमारियों से बचाने कराएं टीकाकरण- पशुपालन विभाग

अनूपपुर। मध्यप्रदेश शासन के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने वर्षा ऋतु के दौरान पशुधन को संक्रामक बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए पशुपालकों एवं किसानों के नाम विशेष स्वास्थ्य एडवायजरी जारी की है। विभाग ने कहा है कि बारिश के मौसम में वातावरण में नमी बढ़ने से पशुओं में संक्रामक रोग तेजी से फैलने की आशंका रहती है। ऐसे में समय पर टीकाकरण और उचित देखभाल ही इन बीमारियों से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। विभाग के अनुसार वर्षा ऋतु में विशेष रूप से गलघोटू (एचएस), लंगड़ा बुखार (बीक्यू), खुरपका-मुंहपका (एफएमडी) तथा लंपी स्किन डिजीज (एलएसडी) जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। गलघोटू रोग में पशु को तेज बुखार, सांस लेने में कठिनाई और गले में सूजन की शिकायत होती है। लंगड़ा बुखार में पैरों में सूजन आने से पशु चलने-फिरने में असमर्थ हो जाता है। खुरपका-मुंहपका रोग में मुंह और खुरों में छाले पड़ने से पशु भोजन नहीं कर पाता, जबकि लंपी स्किन डिजीज में शरीर पर गांठें बनने के साथ लंबे समय तक कमजोरी बनी रहती है। विभाग ने बताया कि ये बीमारियां पशुओं के स्वास्थ्य और कार्यक्षमता को प्रभावित करने के साथ ही दुग्ध उत्पादन में भी कमी लाती हैं, जिससे पशुपालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए सभी पशुपालक अपने पशुओं का नियमित एवं समयबद्ध टीकाकरण अवश्य कराएं। एडवायजरी में पशुशालाओं की नियमित साफ-सफाई, जलभराव से बचाव तथा पशुओं के लिए सूखा और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने की भी सलाह दी गई है। यदि किसी पशु में बीमारी के शुरुआती लक्षण दिखाई दें, तो उसे तत्काल स्वस्थ पशुओं से अलग कर निकटतम शासकीय पशु चिकित्सालय या पशु चिकित्सक से संपर्क कर उपचार कराएं। पशुपालन विभाग ने पशुपालकों से यह भी आग्रह किया है कि मादा पशु के गर्मी (हीट) में आने पर कृत्रिम गर्भाधान (आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन) का ही उपयोग करें। विभाग का कहना है कि इससे नस्ल सुधार के साथ पशुधन की उत्पादकता बढ़ती है और बेहतर गुणवत्ता वाले पशुधन के विकास को बढ़ावा मिलता है।

ट्रेन से नीचे गिरे यात्री की हालत गंभीर

कटनी। ट्रेन के गेट पर बैठा एक यात्री अचानक असंतुलित होकर नीचे गिर गया। इस हादसे में यात्री के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। घायल यात्री की हालत नाजुक बनी हुई है। ट्रेन से यात्री के गिरने की खबर मिलते ही रेलवे अमला तुरंत हरकत में आया और राहत कार्य शुरू किया गया। अमदरा के स्टेशन मास्टर ने कटनी के डिप्टी एसएस कमर्शियल सुरजीत आचार्य को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही डिप्टी एसएस ने सफाई मित्रों को मौके पर भेजा और साथ ही '108 एम्बुलेंस' को कॉल किया। रेलवे टीम और एम्बुलेंस ने बिना देरी किए लहूलुहान हालत में ट्रैक के किनारे पड़े यात्री को उठाया और तत्काल कटनी जिला अस्पताल के लिए रवाना किया। जानकारी के मुताबिक, यात्री की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि हादसे में यात्री के सिर में गहरी चोट आई है और काफी खून बह चुका है। अंदरूनी चोटें अधिक होने के कारण मरीज को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। डॉक्टरों की एक विशेष टीम उसकी जान बचाने के लिए लगातार इलाज में जुटी हुई है।

आवास योजना पर उठे सवाल

टपकती छतें, दरकती दीवारें और अधूरी उम्मीदें

पक्के घर की आस, टपकती झोपड़ियों में कट रही बरसात सरकारी दावों के बीच बेबस गरीब, आवास योजना का लाभ मिलने का इंतजार

मनोज शुक्ला

अनूपपुर। बरसात किसी के लिए राहत लेकर आती है, तो किसी के लिए भय लेकर आती है अनूपपुर नगर पालिका क्षेत्र के सैकड़ों गरीब परिवारों के लिए हर बारिश एक नई परीक्षा बनकर सामने खड़ी है। वर्षों से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर का सपना संजोए बैठे ये परिवार आज भी टपकती झोपड़ियों और जर्जर कच्चे मकानों में जीवन बिताने को मजबूर हैं। योजनाएं कागजों पर आगे बढ़ती दिख रही हैं, लेकिन गरीबों की आंखों में बस इंतजार और निराशा ही दिखाई देती है। सरकारी योजनाओं की सफलता का वास्तविक पैमाना सरकारी फाइलें नहीं, बल्कि उन लोगों की जिंदगी होती है जिनके लिए ये योजनाएं बनाई जाती हैं। अनूपपुर नगर पालिका क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना की तस्वीर इस कसौटी पर कई सवाल खड़े करती है। पात्र हितग्राही वर्षों पहले आवेदन, सत्यापन और सभी औपचारिकताएं पूरी कर चुके हैं, लेकिन पहली किस्त के इंतजार में उनका धैर्य टूटने लगा है। मानसून के बीच जर्जर झोपड़ियों की टपकती छतें, दरकती दीवारें और रातभर जागते परिवार यह याद दिलाते हैं कि विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच अभी भी लंबी दूरी है। प्रशासनिक अव्यवस्था, स्थायी अधिकारियों की कमी और लंबित फाइलों का बोझ उन गरीब परिवारों पर पड़ रहा है, जिनके पास सिर छिपाने के लिए सुरक्षित छत तक नहीं है। यह केवल आवास योजना में देरी का मामला नहीं, बल्कि संवेदनशील प्रशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व की भी परीक्षा है।

हर बारिश के साथ बढ़ता है गरीबों का डर

बारिश की हर बूंद इन परिवारों के लिए राहत नहीं, बल्कि चिंता लेकर आती है। कच्चे मकानों की छतें टपकती हैं, दीवारें कमजोर हो चुकी हैं और कई घर गिरने की कगार पर हैं। रात होते ही परिवार अपने बच्चों, राशन और जरूरी सामान को बचाने की जद्दोजहद में जुट जाते हैं। कई बुजुर्ग और महिलाएं पूरी रात जागकर किसी अनहोनी की आशंका में समय बिताती हैं। एक सुरक्षित घर का सपना अब उनके लिए केवल सरकारी घोषणा नहीं, बल्कि जीवन और सुरक्षा का सवाल बन चुका है।

फाइलों में अटका आवास, उम्मीदों में पसरा सन्नाटा

प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीबों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है, लेकिन अनूपपुर में कई पात्र हितग्राही अब भी पहली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि आवेदन और सत्यापन की सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बावजूद बार-बार केवल आश्वासन ही मिला। दूसरी नगर पालिकाओं में निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं, जबकि यहां लाभार्थी अब भी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। सवाल यह है कि जब योजना स्वीकृत है तो लाभार्थियों तक उसका लाभ समय पर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है।

प्रशासनिक अव्यवस्था का खामियाजा भुगत रहे जरूरतमंद

स्थायी मुख्य नगर पालिका अधिकारी और पर्याप्त लिपिकीय व्यवस्था का अभाव केवल प्रशासनिक समस्या नहीं रह गया है, बल्कि इसका सीधा असर गरीबों के जीवन पर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ-साथ वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा

योजनाएं भी प्रभावित हो रही हैं। जिन लोगों के लिए यह सहायता जीवनयापन का आधार है, वे महीनों तक भुगतान और स्वीकृति के इंतजार में भटक रहे हैं। प्रशासनिक शिथिलता का सबसे बड़ा बोझ हमेशा सबसे कमजोर वर्ग पर ही पड़ता है।

योजनाएं तभी सफल, जब समय पर मिले उनका लाभ

सरकारी योजनाओं का उद्देश्य केवल बजट खर्च करना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाना है। यदि पात्र हितग्राही वर्षों तक पक्के घर की प्रतीक्षा करते रहें और बरसात टपकती झोपड़ियों में गुजारने को मजबूर हों, तो योजनाओं की सफलता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। जरूरत इस बात की है कि प्रशासन लंबित आवास स्वीकृतियों का शीघ्र निराकरण करे, पहली किस्त जारी करे और नगर पालिका की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाए। गरीबों को सहानुभूति नहीं, समय पर उनका अधिकार चाहिए।

अनूपपुर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, कई थाना प्रभारी और पुलिस अधिकारियों के तबादले

पुलिस अधीक्षक विक्रांत मुराब ने जारी किए आदेश

प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए किए गए स्थानांतरण

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। जिले की कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक अनूपपुर द्वारा पुलिस विभाग में व्यापक स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार विभिन्न थानों, पुलिस चौकियों और पुलिस लाइन में पदस्थ अधिकारियों को नवीन पदस्थापना दी गई है। आदेश के तहत निरीक्षक राधिका भगत को पुलिस लाइन से थाना अजाक भेजा गया है। वहीं निरीक्षक (कार्यवाहक) वीरेन्द्र बरकड़े को थाना करनपठार से राजेंद्रग्राम स्थानांतरित किया गया है। उप

निरीक्षक फूलवती अहिरवार को रामनगर से चचाई, उप निरीक्षक सोने सिंह परस्ते को फुनगा पुलिस चौकी से थाना करनपठार, जबकि उप निरीक्षक दयावती मरावी को राजेंद्रग्राम से जैतहरी भेजा गया है। इसके अलावा उप निरीक्षक राघव बागरी को चचाई से रामनगर स्थानांतरित किया गया है, उप निरीक्षक मंगला दुबे को पुलिस चौकी सरई से पुलिस चौकी फुनगा स्थानांतरित किया गया है। सहायक उप निरीक्षकों में रामनारायण तिवारी को थाना कोतमा से पुलिस चौकी फुनगा, पवन प्रजापति को कोतवाली अनूपपुर से पुलिस चौकी सरई, कोमल अरजरिया को फुनगा पुलिस चौकी से कोतवाली अनूपपुर स्थानांतरित किया गया है। आदेश में कुछ स्थानांतरण रिक्त पदों की पूर्ति तथा कुछ प्रशासनिक आवश्यकता एवं कार्य सुविधा को ध्यान में रखते हुए किए जाने का उल्लेख किया गया है। पुलिस अधीक्षक विक्रांत मुराब द्वारा 30 जून को जारी इस आदेश के तत्काल प्रभाव से लागू होने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि इस फेरबदल से पुलिस कार्यप्रणाली में और अधिक गति आएगी तथा जिले में कानून-व्यवस्था को बेहतर ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी।

रेलवे की नई आरक्षण समय-सारिणी पर उठे सवाल

बड़े स्टेशनों में सिर्फ 6 घंटे तो छोटे स्टेशनों में 8 घंटे सेवा

अनूपपुर। बिलासपुर रेल मंडल द्वारा 1 जुलाई से लागू की गई नई पीआरएस (पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम) समय-सारिणी को लेकर यात्रियों और रेलवे संघर्ष समिति ने गंभीर आपत्ति जताई है। आरोप है कि महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर आरक्षण काउंटरों का समय घटाकर मात्र छह घंटे कर दिया गया है, जबकि कई छोटे स्टेशनों पर लगातार आठ घंटे तक आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसे रेलवे की विसंगतिपूर्ण नीति बताते हुए पूर्व व्यवस्था बहाल करने की मांग उठाई गई है। रेलवे संघर्ष समिति के संयोजक अधिवक्ता वासुदेव चटर्जी ने कहा कि लंबे प्रयासों के बाद अनूपपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आरक्षण काउंटर का समय बढ़ाया गया था, लेकिन अब बिलासपुर मंडल के अधिकारियों ने नई समय-सारिणी लागू कर उसे फिर कम कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत अनूपपुर, उमरिया और अंबिकापुर जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर आरक्षण सुविधा दो पालियों में संचालित होगी। पहली पाली चार घंटे और दूसरी पाली दो घंटे की रहेगी, यानी कुल छह घंटे ही आरक्षण उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि अनूपपुर एक प्रमुख जंक्शन स्टेशन है, जबकि उमरिया विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ पर्यटन क्षेत्र का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। वहीं अंबिकापुर में भविष्य में वाशिंग पिट बनने के बाद लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन की संभावनाएं हैं। ऐसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर आरक्षण समय

कम करना यात्रियों के हित में नहीं है। समिति का कहना है कि दूसरी ओर कई छोटे रेलवे स्टेशनों पर लगातार आठ घंटे तक आरक्षण सुविधा जारी रखी गई है। इससे यह सवाल उठता है कि अधिक यात्री भार वाले स्टेशनों की बजाय कम व्यस्त स्टेशनों को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है। नई व्यवस्था से यात्रियों को टिकट आरक्षण के लिए अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बिलासपुर-कटनी रेलखंड के करगी रोड, अनूपपुर जंक्शन, अमलाई, बुढार, बिरसिंहपुर, उमरिया और चंदिया सहित सीआईसी रेलखंड के अंबिकापुर, मनेन्द्रगढ़, बिजुरी एवं कोतमा स्टेशनों पर आरक्षण समय में बदलाव किया गया है। रेलवे संघर्ष समिति ने बिलासपुर जोन एवं रेल मंडल प्रशासन से मांग की है कि अनूपपुर, उमरिया और अंबिकापुर जैसे प्रमुख स्टेशनों पर आरक्षण काउंटर का समय पूर्ववत किया जाए, ताकि यात्रियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े और उन्हें बेहतर रेल सेवाएं मिल सकें।

जिला न्यायालय परिसर में पौधरोपण एवं विधिक साक्षरता शिविर हुआ आयोजित

अनूपपुर। पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन एवं हरित वातावरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय परिसर, अनूपपुर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती माया विश्वलाल के नेतृत्व में वृक्षारोपण कार्यक्रम एवं पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन विषयक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती माया विश्वलाल द्वारा पौधरोपण कर किया। उन्होंने उपस्थितजनों से पर्यावरण संरक्षण को जन-आंदोलन का स्वरूप देने तथा अधिक से अधिक पौधे लगाने एवं उनके संरक्षण का संकल्प लेने का आहवान किया। कार्यक्रम में एक्सीलेंस तुलसी कॉलेज, अनूपपुर के छात्र-छात्राओं, एनसीसी एवं एनएसएस के स्वयंसेवकों तथा मूक-बधिर दिव्यांगजनों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए पौधरोपण किया। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती माया विश्वलाल तथा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रावेन्द्र कुमार सोनी ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पर्यावरण का संरक्षण केवल व्यक्तिगत दायित्व नहीं, बल्कि सामाजिक एवं नैतिक उत्तरदायित्व भी है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण भावी पीढ़ियों के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला है। इस अवसर पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों को पर्यावरण संरक्षण एवं पौधों के नियमित संरक्षण का संकल्प भी दिलाया। कार्यक्रम में जिले के वाक एवं श्रवण बाधित दिव्यांगजनों ने भी सक्रिय सहभागिता करते हुए वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का प्रेरक संदेश दिया। कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय गंगाचरण दुबे, जिला न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती चैनवती ताराम, न्यायाधीश सुश्री सुधा पाण्डेय, न्यायाधीश बॉबी सोनकर, न्यायाधीश सुश्री सृष्टि साहू, ट्रेनी जज अर्पण चौधरी, जिला विधिक सहायता अधिकारी ब्रजेश पटेल, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल संतदास नापित, सहायक प्राध्यापक डॉ. तरन्नुम सहित न्यायालय के अधिकारी-कर्मचारी, एनसीसी एवं एनएसएस के विद्यार्थी तथा बड़ी संख्या में मूक-बधिर दिव्यांगजन उपस्थित रहे।

सामाजिक एकता के संकल्प के साथ अमरकंटक में विप्र समाज का हुआ संगम

संगठन विस्तार की बनी रणनीति

अमरकंटक। पवित्र नगरी अमरकंटक स्थित शांति कुटीर में बुधवार सायंकाल विप्र समाज की एक महत्वपूर्ण परिचयात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य समाज के विभिन्न परिवारों के बीच आत्मीय परिचय स्थापित करना, संगठनात्मक एकजुटता को सुदृढ़ करना तथा सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जनहितकारी गतिविधियों को नई दिशा प्रदान करना रहा। बैठक में उपस्थित विप्र समाज के सदस्यों ने एक-दूसरे से परिचय प्राप्त करते हुए समाज को अधिक संगठित, सक्रिय एवं प्रभावी बनाने पर गंभीर मंथन किया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समाज के बीच निरंतर संवाद बनाए रखने तथा संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने के लिए प्रत्येक माह नियमित बैठक आयोजित की जाएगी। चर्चा के दौरान सामाजिक समरसता, आपसी सहयोग, युवा पीढ़ी की सक्रिय भागीदारी तथा समाज के प्रत्येक परिवार को संगठन से जोड़ने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से

विचार-विमर्श किया गया। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में सामाजिक एकता ही समाज की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि सभी सदस्य एक मंच पर संगठित होकर कार्य करें तो समाज न केवल अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को सहेज सकेगा, बल्कि जनकल्याण एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्यों में भी प्रभावी भूमिका निभा सकेगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों का नियमित आयोजन कर समाज के सभी वर्गों, विशेषकर युवाओं और नई पीढ़ी को संगठन से जोड़ा जाएगा। वरिष्ठजनों ने संगठन की मजबूती के लिए आपसी विश्वास, समन्वय एवं निरंतर संवाद को समय की आवश्यकता बताया तथा सभी परिवारों से सक्रिय सहभागिता का आहवान किया। बैठक में अंबिका तिवारी, रामगोपाल द्विवेदी, रामसरोवर द्विवेदी, धनंजय तिवारी, श्रवण उपाध्याय, उमाशंकर पांडे, ओ.पी. गौतम, मुनीश पांडेय, नर्मदा प्रसाद पाठक, मुकेश उपाध्याय, रामनरेश दुबे, सोमू दुबे, पवन दुबे, संतोष तिवारी, शिवप्रसाद त्रिपाठी, कमलेश द्विवेदी, अखिलेश द्विवेदी, लखन प्रसाद द्विवेदी, सीताप्रसाद पाठक, राजेश पाठक, राकेश उपाध्याय, मुकेश पाठक, संदीप कुमार ज्योतिषी तथा बालकृष्ण गौतम सहित बड़ी संख्या में विप्र समाज के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक का समापन समाज की एकता, संगठन की निरंतर मजबूती तथा आगामी माह पुनः बैठक आयोजित करने के सर्वसम्मत संकल्प के साथ हुआ। उपस्थित सभी सदस्यों ने विश्वास व्यक्त किया कि नियमित संवाद एवं सामूहिक प्रयासों से विप्र समाज सामाजिक, सांस्कृतिक और जनसेवा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।

मूंग-उड़द खरीदी के लिये 7 उपार्जन केंद्र निर्धारित

हरिभूमि न्यूज ▶▶ कटनी

राज्य शासन के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के निर्देशानुसार वर्ष 2025-26 (विपणन वर्ष 2026-27) के लिए समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द का उपार्जन 1 जुलाई से प्रारंभ हो गया है, जो 10 अगस्त 2026 तक जारी रहेगा। कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देशानुसार जिले में किसानों की सुविधा के लिए 7 उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां समर्थन मूल्य पर मूंग एवं उड़द की खरीदी की जाएगी।सरकार द्वारा इस वर्ष एफएक्यू (**FAQ**) गुणवत्ता वाली मूंग का समर्थन मूल्य 8,767 रुपये प्रति क्विंटल तथा उड़द का समर्थन मूल्य 7,800 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।कलेक्टर श्री तिवारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कटनी तहसील के लिए प्राथमिक कृषि साख समिति कैलवाराकला द्वारा **CWC** परिसर इमलिया में खरीदी की जाएगी। ढीमरखेड़ा तहसील में प्राथमिक कृषि साख समिति पान उमरिया द्वारा राधेकृष्ण वेयरहाउस, बड़वारा तहसील में प्राथमिक कृषि साख समिति विलायतकला द्वारा पंचमुखी वेयरहाउस बसाड़ी, बहोरीबंद तहसील में प्राथमिक कृषि साख समिति हथियागढ़ द्वारा जय रूपनाथ वेयरहाउस बचैया ब्रदर्स वेयरहाउस स्लीमनाबाद में खरीदी की जाएगी।

अमृत स्टेशन विकास योजना से बदल रही रेलवे स्टेशनों की तस्वीर

उत्कृष्ट कार्यों के लिए सीपीएम राजीव कुमार सम्मानित

अनूपपुर। भारतीय रेल अमृत स्टेशन विकास योजना के माध्यम से आधुनिक सुविधाओं के नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। इस योजना के तहत अनूपपुर, शहडोल और उमरिया रेलवे स्टेशनों का तेजी से कायाकल्प किया जा रहा है। पहले जहां स्टेशन परिसरों में संकरी और अव्यवस्थित व्यवस्था थी, वहीं अब यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चौड़ी सड़कों, आधुनिक सर्कुलेटिंग एरिया, रिंग रोड, हाईमास्ट एवं आकर्षक लाइटिंग तथा विभिन्न वाहनों के लिए विशाल पार्किंग का निर्माण किया गया है। अमृत स्टेशन विकास योजना के अंतर्गत जिन स्थानों पर पुराने पार्क, रेलवे आवास और कार्यालयों को हटाया गया था, उनकी जगह रेलवे कॉलोनी में नए पार्क, आधुनिक रेलवे आवास एवं नवीन कार्यालय भवनों का निर्माण कराया गया है। अधिकारियों के अनुसार, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर (सीपीएम) राजीव कुमार के पदभार संभालने के बाद योजना के कार्यों में उल्लेखनीय तेजी आई है, जिससे निर्धारित समय में विकास कार्य पूरे करने की दिशा में प्रगति हो रही है। योजना के दूसरे चरण में पुराने स्टेशन भवनों के स्थान पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए स्टेशन भवन विकसित किए जाएंगे। इनमें व्यावसायिक गतिविधियों के लिए दुकानें, यात्री

लाउंज, विश्राम गृह सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं सर्कुलेटिंग एरिया में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बाद सुलभ शौचालय सहित अन्य जनसुविधाओं का भी निर्माण प्रस्तावित है। इधर, इन विकास कार्यों के सफल क्रियान्वयन एवं उत्कृष्ट योगदान के लिए 1 जुलाई को बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम में साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर कांग्रेस मंडल बिलासपुर ने चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर राजीव कुमार एवं वरिष्ठ मंडल अभियंता (समन्वय) अरविंद विश्वकर्मा का सम्मान किया। यह सम्मान वरिष्ठ मंडल अभियंता (समन्वय) के बिलासपुर स्थित चेंबर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया गया। इस अवसर पर मंडल समन्वयक विजय अग्निहोत्री, जोनल कार्यकारी सीआईसी प्रभारी अध्यक्ष लक्ष्मण राव, अतिरिक्त संयुक्त महामंत्री शुभम उपाध्याय तथा रायगढ़ शाखा सचिव संजय श्रीवास्तव सहित रेलवे मजदूर कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित रहे। पदाधिकारियों ने दोनों अधिकारियों के नेतृत्व में अमृत स्टेशन विकास योजना के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ रेलवे स्टेशनों का स्वरूप भी आधुनिक और आकर्षक बन रहा है। यदि चाहें तो मैं इसके लिए हरिभूमि शैली की और अधिक प्रभावशाली मुख्य हेडलाइन, सब हेडिंग और इंट्रो भी तैयार कर सकता हूँ।